राजस्थान में ''वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट'' को बढ़ावा दिया जायेगा-भजनलाल

मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया युनिवर्सिटी गेम्स के जयपुर में आयोजन के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये

जयपुर 18 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को खेलों के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए गांवों से लेकर कस्बों तक श्रेष्ठ खेल सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने युवा मामले एवं खेल विभाग के अधिकारियों को ''खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स - 2025'' के सफल आयोजन के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने के लिए निर्देशित किया। शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में युवा मामले एवं खेल विभाग की बजट घोषणाओं और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स - 2025 की कार्ययोजना के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।

■ **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिये कि इस आयोजन की तैयारियों में किसी भी स्तर पर कोताही नहीं बरती जाये तथा श्रेष्ठ सुझावों को समाहित करते हुए आयोजन की रूप रेखा बनाई जाये।**

उन्होंने कहा कि यह गर्व का विषय है कि प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जा रहा है जिसमें देश-प्रदेश से हजारों प्रतिभाशाली खिलाड़ी शिरकत करेंगे।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आयोजन की तैयारियों में किसी भी स्तर पर कोताही नहीं बरती जाए और श्रेष्ठ सुझावों को समाहित करते हुए आयोजन की रूपरेखा बनाई जाए।

उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स से पूर्व की समयावधि में प्रदेशभर में पंचायत स्तर तक खेलों का अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए। साथ ही, उपखण्ड एवं जिला स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाए।

शर्मा ने कहा कि राज्य में विभिन्न खेलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने ''वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट'' की अवधारणा के तहत प्रत्येक जिले में एक खेल को विशेष रूप से बढ़ावा देने का फैसला किया है। इससे प्रदेश में अलग-अलग खेलों में बेहतरीन खिलाड़ी तैयार हो सकेंगे। उन्होंने प्रत्येक जिले में खेल विशेषज्ञों को संयोजक के रूप में नियोजित करने के संबंध में कार्यवाही करने के निर्देश दिए जो अपने जिले में प्रतिभाओं को तलाशेंगे। बैठक में युवा मामले एवं खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित विभाग के उच्च अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को युवा मामले एवं खेल विभाग की बजट घोषणाओं और ''खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स- 2025'' की कार्ययोजना की समीक्षा की।

पुतिन ने प्र.मंत्री मोदी को फोन किया

नई दिल्ली, 18 अगस्त। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी को फोन किया। फोन कॉल पर पुतिन ने पीएम मोदी को अलास्का में ट्रंप के साथ हुई बैठक के बारे में जानकारी दी। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में पुतिन के साथ हुई बातचीत की जानकारी दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन को उनके फोन कॉल और अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी हालिया मुलाकात के बारे में जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। भारत ने यूक्रेन विवाद के शांतिपूर्ण समाधान का लगातार आ ान किया है। इस संबंध में सभी प्रयासों का भारत समर्थन करता है। मैं

■ **अलास्का में ट्रंप के साथ हुई वार्ता के बारे में जानकारी दी।**

आने वाले दिनों में हमारे निरंतर आदान-प्रदान की आशा करता हूं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 15 अगस्त को अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक की थी। इस बैठक में यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर चर्चा की गई। हालांकि, इसमें रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में संघर्ष विराम लागू करने पर सहमति नहीं बनी।यह बैठक ऐसे वक्त में हुई थी जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया है। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी और अमेरिका के कदम को अन्यायपूर्ण और बेतुका करार दिया था।

'भारत पर ''डबल पैनल्टी''...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जिस समय पर यह हुआ है वो भी महत्वपूर्ण है। यह बहस ऐसे समय हो रही है जब राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप मास्को के साथ रिश्तों को फिर से आकार देने की कोशिश कर रहे हैं। अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी चर्चित बैठक से यूक्रेन को लेकर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, लेकिन ट्रंप ने इन वार्ताओं को "10/10" बताया और इसे रणनीतिक बदलाव की दिशा में कदम करार दिया। एक अन्य इंटरव्यू में उन्होंने यहां तक कहा कि वह सेकेंडरी सैंक्शन लगाने में देर कर सकते हैं: ''मुझे इस पर दो या तीन हफ़्तों तक सोचना पड़ सकता है... अगर मैं अभी सेकेंडरी सैंक्शन लगाता हूँ तो यह उनके लिए विनाशकारी होगा।''

ट्रंप ने यहां तक दावा किया कि भारत पर लगाए गए टैरिफ ने रूस को बातचीत के लिए मजबूर किया। उनका कहना था कि रूस को उसके दूसरे सबसे बड़े ग्राहक से वंचित करके वॉशिंगटन ने दबाव बनाया। लेकिन भारत ने इस दावे को नकार दिया और कहा कि रूस से उसका ऊर्जा व्यापार जारी है और मॉस्को का अमेरिका से संपर्क इससे जुड़ा हुआ नहीं है।

भारत के लिए यह दुविधा गंभीर है। एक ओर उसकी ऊर्जा सुरक्षा सस्ते तेल पर निर्भर है, और पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूसी तेल रियायती दरों पर मिल रहा है। दूसरी ओर, अमेरिकी टैरिफ बढ़ते व्यापार, तकनीकी और सुरक्षा सहयोग को नुकसान पहुँचा रहे हैं। खासकर चीन से अलग तरह के बर्ताव ने नई दिल्ली में असंतोष बढ़ा दिया है।

वॉशिंगटन के लिए स्थिति और भी कठिन है। भारत को दंडित करके ट्रंप अपनी सख्ती दिखा सकते हैं, बिना वैश्विक तेल प्रवाह को बाधित किए, लेकिन इससे एक अहम रणनीतिक साझेदार दूर हो सकता है। वहीं, चीन को बख़्शने से वैश्विक कीमतें स्थिर रहती हैं, लेकिन अमेरिकी सैंक्शन नीति की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो जाते हैं।

अंततः, यह नीति सिद्धांत और व्यावहारिकता के बीच फँसी हुई दिखती है। भारत को निशाना बनाकर और चीन को छोड़कर, वॉशिंगटन शायद अल्पकालिक राजनीतिक लक्ष्य हासिल कर ले, लेकिन इससे अपने सबसे अहम सहयोगी के साथ विश्वास कमजोर पड़ सकता है। जैसे ही ट्रंप मॉस्को से नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं और चीन को सैंक्शन के घेरे से बाहर रख रहे हैं, भारत एक बार फिर दो बड़ी ताक़तों के बीच दबाव में आ गया है, जहां उसकी व्यावहारिकता को तो सज़ा मिल रही है, जबकि दूसरों को छूट।

अशोक गहलोत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्टडी सर्कल में सक्रिय हैं और गहलोत के क़रीबी माने जाते हैं। ख़बर है कि गहलोत सोनिया गांधी से मुलाक़ात की कोशिश में गहलोत राजीव गांधी फ़ाउंडेशन का सहारा ले रहे हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि उनकी यह कोशिश एक बार फिर बेकार साबित हो सकती है। गहलोत के अब भी एआईसीसी में कई दोस्त मौजूद हैं जो उनकी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन दुर्भाग्य से सोनिया गांधी और राहुल गांधी उनमें शामिल नहीं हैं।

जर्जर स्कूलों की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मामले में शिक्षा मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय, मुख्य सचिव, एसीएस शिक्षा, प्रमुख बाल कल्याण सचिव और राष्ट्रीय बाल आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है था। हाईकोर्ट की एक अन्य एकलपीठ ने स्कूल भवनों के हालातों को लेकर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया था।

अलास्का बैठक में ट्रम्प...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पुतिन युद्धिवराम और शांति के लिए नहीं मानते उन पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। उन्होंने विश्व स्तर पर कोई द्वितीयक प्रतिबंध लागू नहीं किया है।

अब ट्रंप के पास एक ही विकल्प बचता है, यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेन्स्की को रूस को पर्याप्त ज़मीनी रियायतें देने के लिए राज़ी करना, जिसमें क्रीमिया और डोनबास क्षेत्र के बड़े हिस्से शामिल हैं।

अगर किसी और वैकल्पिक शांति फॉर्मूले की गुंजाइश नहीं बनती, तो इस पूरी प्रक्रिया के रूसी राष्ट्रपति पुतिन प्रमुख विजेता के रुप में उभरते हैं। अमेरिका अपने पहले के रुख से पीछे हट गया है और लगभग वह सब कुछ मान रहा है जो रूस मांग रहा था। यहाँ तक कि वह यूक्रेन को भविष्य में सुरक्षा गारंटी देने के लिए रूस की सहमति भी चाह रहा है।

इसके बदले में, रूस यूक्रेन के बड़े भू-भाग, क्रीमिया (जो लंबे समय से विवाद का विषय रहा है), और यूक्रेन को स्थायी रूप से नाटो से बाहर रखने की मांग कर रहा है, हालांकि पुतिन को एक ही नुकसान हुआ, वह यूक्रेन की संप्रभु पहचान को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सके। उनका मानना था कि यूक्रेन एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में रहने के लायक नहीं है।

कुछ पश्चिमी विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप ने पुतिन को उस स्थिति में भी इनाम दे दिया, जब उन्होंने अमेरिकी युद्धिवराम और शांति की समयसीमा को स्वीकार नहीं किया।

भले ही यूक्रेन में शांति स्थापित हो जाए, यह देखना बाकी है कि भारत-अमेरिका संबंधों को पहले जैसे सौहार्दपूर्ण स्तर पर कैसे लौटाया जा सकता है। यदि शांति समझौता होता है, तो भारत पर लगाए गए द्वितीयक प्रतिबंध निश्चित रूप से हटा लिए जाएंगे, लेकिन दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंध - खासकर मोदी और ट्रंप के बीच कथित व्यक्तिगत संबंध - शायद ही पूरी तरह से बहाल हो पाएंगे। यूक्रेन में शांति के लिए भारत को कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन शायद यह कीमत वैश्विक मंच पर एक उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए चुकाना उचित कदम हो।

इण्डिया गठबन्धन मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एक लोकसभा सांसद ने कहा, ''प्रस्ताव पारित होता है या नहीं, उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम अपना विरोध दर्ज कराएं।

सी ई सी सवालों का जवाब देने के बजाय विपक्ष पर उंगली उठा रहे हैं।'' इस बीच, राहुल गांधी ने आज कहा कि मतदाता सूचियों की पूनरीक्षण प्रक्रिया ''वोट चोरी'' का एक ''नया हथियार'' है और उन्होंने ''एक व्यक्ति, एक वोट'' के सिद्धांत की रक्षा करने का संकल्प लिया।

उन्होंने यह टिप्पणी अपने वॉट्सऐप चैनल पर एक पोस्ट में की, जहाँ उन्होंने उन लोगों से अपनी मुलाकात का ज़िक्र किया जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में मतदान किया था लेकिन बिहार में पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान उनके नाम सूची से हटा दिए गए। कांग्रेस नेता ने रविवार को बिहार के सासाराम में अपनी वोट अधिकार यात्रा के शुभारंभ के दौरान इस समूह से मुलाकात की।

उन्होंने हिंदी में पोस्ट करते हुए लिखा, एस आई आ '' वोट चोरी का नया हथियार है। संयोग से, इस तस्वीर में मेरे साथ खड़े ये लोग इस चोरी के जीते-जागते सबूत हैं।''

उन्होंने कहा, ''इन सभी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान किया था - लेकिन जब बिहार विधानसभा चुनाव आए, तो इनके नाम, इनकी पहचान, इनका अस्तित्व भारतीय लोकतंत्र से मिटा दिया गया।''

उन्होंने पूछा, ''क्या आप जानते हैं ये लोग कौन हैं? ये हैं - राज मोहन सिंह (70); किसान और सेवानिवृत्त सैनिक उमरावती देवी (35); दलित और मजदूर; धनंजय कुमार बिंद (30); पिछड़ा वर्ग और मजदूर; सीता देवी (45); महिला और पूर्व मनरेगा मजदूर; राजू देवी (55); पिछड़ा वर्ग और मजदूर मोहम्मद अंसारी (52); अल्पसंख्यक और मजदूर''।

राहुल गांधी ने कहा, ''भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत इन्हें बहुजन और गरीब होने की सजा दे रही है - यहाँ तक कि हमारे सैनिकों को भी नहीं बख्शा है।

उन्होंने कहा, ''अब इनके पास न तो वोट होगा, न पहचान और न ही अधिकार।''

सामाजिक भेदभाव और बदहाल आर्थिक स्थिति के कारण वे व्यवस्था की साजिश के खिलाफ लड़ने में असमर्थ हैं।

हम यहां उनके साथ खड़े हैं ताकि एक व्यक्ति, एक वोट के सबसे बुनियादी अधिकार की रक्षा कर सकें।''

राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव और विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी ने बिहार के औरंगाबाद में देवकुंड सूर्य मंदिर में पूजा की, जब उनकी वोट अधिकार यात्रा अपने दूसरे दिन में प्रवेश कर रही थी।

कटुंबा से यात्रा शुरू होकर यह सोमवार शाम गया पहुंचेगी। यह यात्रा 16 दिन बाद एक सितंबर को पटना में एक रैली के साथ समाप्त होगी यह यात्रा पैदल और वाहन दोनों माध्यमों से हाइब्रिड मोड में की जा रही है, ठीक वैसे ही जैसे लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी।

यात्रा औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, छपरा और आरा से गुजरेगी। रविवार को, ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के अन्य सदस्यों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल को दो विकल्पों की बात दोहराई।

आपको या तो शपथपत्र देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। तीसरा कोई विकल्प नहीं है।

यदि सात दिनों के भीतर शपथपत्र नहीं दिया गया, तो इसका मतलब है कि आरोप निराधार हैं, कुमार ने कहा 7 अगस्त को, राहुल गांधी ने बेंगलुरु की एक लोकसभा सीट के अंतर्गत एक विधानसभा क्षेत्र से एकत्रित आंकड़ों के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की थी कि कैसे मतदाता सूची में हेरफेर की जा रही है उन्होंने कहा इसका उद्देश्य भाजपा को फायदा पहुंचाना बताया।

रिटायर्ड कैप्टन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एक्सप्रेस-हाईवे अंडरपास के पास कार रोकी। लोगों ने गांधी पथ क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहनों पर सख्ती से कार्रवाई और नियमित जांच की मांग की है।

लोगों ने कार की फोटो खींचकर पुलिस को भेजी थी। इस आधार पर नंबर ट्रेस कर मालिक की पहचान की गई।

राष्ट्रदूत हिन्दु संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाईन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513 कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908